



परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास



परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

1. कोयला खान क्षेत्र में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना का विकास –

कोयला नियंत्रक कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 और कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 12सी के तहत गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय सुरक्षात्मक कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्य, कोलफील्ड्स क्षेत्रों में सड़क और रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में कोयला कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त करता है और आवेदनों/दावों की जांच करता है ताकि सीसीडीएसी के माध्यम से धनराशि जारी की जा सके।

वर्ष 2023–24 के लिए दो योजनागत योजनाओं का बजट निम्नानुसार है:

कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा –20.00 करोड़ रुपये

कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास –72.00 करोड़ रुपये

वर्ष 2023–24 से संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 10.34 करोड़ रुपये तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 86.26 करोड़ रुपये की स्पिलओवर राशि थी।

88वीं सीसीडीए समिति ने संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 70.78 लाख रुपये तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 23.418 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023–24 में संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 19.9604 करोड़ रुपये तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 66.5828 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल): रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं

भविष्य में उत्पादन और निकासी में नियोजित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, सीआईएल ने प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है। इन रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को या तो भारतीय रेलवे (जमा आधार पर) या रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली इरकॉन, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व) और संबंधित राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तीन (03) प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाएं जमा आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं और चार (04) रेल अवसंरचना परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

2.1 जमा आधार:

पूर्व मध्य रेलवे, पटना झारखंड में सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के लिए लगभग 44.37 किलोमीटर लंबी टोरी शिवपुर नई बीजी लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसकी परियोजना लागत रु. 3587.37 करोड़ है। पूरी लाइन का दोहरीकरण दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस नई बीजी लाइन के माध्यम से कोयला भेजा जा रहा है। इस रेल लाइन की क्षमता को 65 एमटीपीए से बढ़ाकर 100 एमटीपीए करने के लिए इसका तिहरीकरण करने का काम शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 01.03.2024 को किया जाएगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एमसीएल की आईबी वैली कोलफील्ड्स के लिए लगभग 52.41 किलोमीटर की लंबाई के साथ झारसुगुड़ा-बरपाली – सरडेगा रेल अवसंरचना परियोजना को 1123.90 करोड़ रु. की लागत से क्रियान्वित किया है और यह लाइन



अप्रैल-2018 में चालू हो गई है। बरपाली में लोडिंग बल्ब के साथ इस रेल मार्ग का दोहरीकरण और रेल फ्लाईओवर परिसर सहित झारसुगुड़ा यार्ड के रीमॉडलिंग को मंजूरी दी गई है और 3200 करोड़ रु. की अनुमानित पूंजी पर निष्पादन के अधीन है। इससे रेलवे लाइन की कोयला निकासी क्षमता 34 एमटीपीए से बढ़कर 65 एमटीपीए हो जाएगी। झारसुगुड़ा- बरपाली - सरडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण दिनांक 03.02.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू और उद्घाटन किया गया है। रेलवे द्वारा बारापाली में बल्ब और झारसुगुड़ा में फ्लाईओवर कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और इसके जून 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

2.2 संयुक्त उद्यम आधार -

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जीसीआरएल) - 49.085 किलोमीटर लंबे शिवपुर-कठौतिया खंड का निर्माण झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जीसीआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सीसीएल, इरकॉन और झारखंड राज्य सरकार भागीदार हैं, जिसकी अनुमानित लागत 1799.64 करोड़ रु. है। मई 2022 में वित्तीय समापन प्राप्त हुआ। परियोजना निर्माणाधीन है और वर्तमान प्रगति लगभग 52% है और इसके जून 2025 तक चालू होने का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल) - एसईसीएल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दो चरणों में ईस्ट रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य कर रही है:

चरण 1: स्पर के साथ खरसिया-धरमजयगढ़ से गारे पलमा और लगभग 132 किलोमीटर की तीन फीडर लाइनों के साथ, जिसकी अनुमानित लागत 3055 करोड़ रु. है। खरसिया से धरमजयगढ़ (74 किमी) के बीच मुख्य रेल कॉरिडोर, धारगोडा और भालूमंडा (13.873 किमी) के बीच स्पर लाइन और छाल (8.429 किमी) और बरौड (4.139 किमी) के लिए फीडर लाइन को दिनांक 14.09.2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू और उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में इस नई बीजी रेलवे लाइन के माध्यम से कोयले की निकासी की जा रही है। भालूमंडा और गारे पलमा (17 किमी) के बीच स्पर लाइन और

दुर्गापुर (7 किमी) के लिए फीडर लाइन का शेष कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

चरण II: लगभग 62.5 किलोमीटर की लंबाई वाली धरमजयगढ़ - कोरबा इस सड़क की अनुमानित लागत 1686.22 करोड़ रु. है। दिनांक 28.08.2023 को वित्तीय समापन प्राप्त हो गया है। वर्तमान में, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। कुल निजी भूमि (290.698 हेक्टेयर) का अधिग्रहण किया जा चुका है। इरकॉन द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना के अगस्त 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)- एसईसीएल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दिपका, कटघोरा, सिंदूरगढ़ और पासन के माध्यम से ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर (गेवरा रोड से पेंद्रा) का निर्माण कर रही है, जिसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर और फीडर लाइनें लगभग 35 किलोमीटर हैं, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 4970.11 करोड़ रु. है। इससे कोरबा कोलफील्ड्स से लगभग 65 एमटीपीए कोयले की निकासी हो सकेगी। रेल लाइनों के निर्माण के लिए निविदाएँ प्रदान की जा चुकी हैं और निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान प्रगति लगभग 69.4% है और इसके दिसंबर 2024 तक चालू होने का अनुमान है।

महानदी रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)- एमसीएल, इरकॉन और ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी, कोयले की निकासी के लिए एमसीएल के तलचर कोलफील्ड्स में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण का कार्य कर रही है। एमसीएल के तलचर कोलफील्ड्स में 69.10 किलोमीटर लंबाई के साथ अंगुल-बलराम - झारपड़ा - तेंतुलोई लिंक (जिसमें 14.22 किलोमीटर लंबाई का झारपड़ा - कलिंगा- अंगुल लिंक शामिल है) की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रु. (भूमि की लागत को छोड़कर) है।

पहले चरण में, 14.22 किलोमीटर लंबे अंगुल -बलराम खंड को 145 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत से चालू किया गया है। इससे तलचर कोयला क्षेत्र से लगभग 15 एमटीपीए की निकासी क्षमता प्राप्त हुई है।



दूसरे चरण में बलराम— पुटागड़िया — जरापाड़ा—तेनतुलोई रेल लाइन का निर्माण करने की योजना है। इस परियोजना को रेल मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी) ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। शेष भूमि अधिग्रहण का काम रेलवे द्वारा समय रहते पूरा कर लिया जाएगा।

2.3 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं —

सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लदान प्रणाली को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं। इन अवसंरचना परियोजनाओं से कोयले की गुणवत्ता में सुधार, अंडर-लोडिंग शुल्क में बचत और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

एफएमसी चरण-I: एफएमसी चरण-I में, सीआईएल ने 4 मि.ट. प्रति वर्ष और उससे अधिक क्षमता वाली खानों में 382.5 एमटीपीए क्षमता की 33 परियोजनाओं की पहचान की है। इन 33 एफएमसी परियोजनाओं में से, 200.5 एमटीपीए क्षमता की 15 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और शेष 18 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। चरण-I की सभी एफएमसी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2024-2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

एफएमसी चरण-II: एफएमसी चरण-II में 57 एमटीपीए की 8 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिनमें से 34.5 एमटीपीए की कुल 6 एफएमसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। शेष 2 परियोजनाएं निर्माण और निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। सभी चरण-II एफएमसी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2025-2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

एफएमसी चरण-III: एफएमसी चरण-III में 324 एमटीपीए की 17 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिनमें से 5 एमटीपीए क्षमता की 1 एफएमसी परियोजना निर्माणाधीन है और 40 एमटीपीए की 2 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। शेष 14 परियोजनाएं अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। सभी चरण-III एफएमसी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2028-2029 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

एफएमसी चरण-IV: एफएमसी चरण-IV में 74 एमटीपीए क्षमता की 14 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिनमें से 14 एमटीपीए क्षमता की 2 एफएमसी परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। शेष 12 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। सभी चरण-III एफएमसी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2029-2030 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

ये एफएमसी परियोजनाएं वित्त वर्ष 2029-2030 तक मशीनीकृत निकासी को 151 एमटीपीए से बढ़ाकर 988.5 एमटीपीए तक करने में सक्षम होंगी।

एससीसीएल द्वारा किए गए प्रयास—

रेत भण्डारण:

सार्वजनिक इमारतों, कॉलोनियों, रेल लाइनों, सार्वजनिक सड़कों आदि जैसी महत्वपूर्ण सतही विशेषताओं की सुरक्षा के लिए, भूमिगत रिक्त स्थान/गोफ (कोयला निष्कर्षण के बाद) को नदी की रेत से भर (भण्डारण) दिया जाता है। रेत की अत्यधिक कमी के कारण, एससीसीएल खानों में रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में भण्डारण के लिए बॉटम ऐश, बॉयलर ऐश और क्रशड ओवरबर्डन सामग्री आदि जैसी अन्य सामग्रियों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षण किए जा रहे हैं।

अब तक एससीसीएल की खानों में 47.04 लाख घन मीटर प्रसंस्कृत ओवरबर्डन का उपयोग किया जा चुका है। एससीसीएल की 12 भूमिगत खानों में नदी की रेत, बॉटम ऐश और प्रसंस्कृत ओवरबर्डन का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में भूमिगत खानों में 29% पीओबी, 50% बॉटम ऐश और लगभग 21% रेत का उपयोग किया जा रहा है।

कोयला निकासी के लिए रेल और अवसंरचना परियोजना:

कोयला उत्पादन की योजनाबद्ध आकर्षण को ध्यान में रखते हुए, एससीसीएल की कोयला प्रेषण क्षमता 100 मीट्रिक टन है। एससीसीएल द्वारा कोयला निकासी और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं —

कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी): 10 सीएचपी और एक वार्फ लोडिंग प्रणाली है जिसकी कुल क्षमता 74 मीट्रिक



टन है जो रेल/एमजीआर प्रणाली द्वारा डिस्पैच करता है। 10 प्री-वे वैगन लोडिंग प्रणाली और 19 प्री-वे ट्रक लोडिंग प्रणाली विभिन्न खानों और कोयला हैंडलिंग प्लांट में स्थापित और काम कर रहे हैं।

नैनी कोल ब्लॉक के लिए, 68 किलोमीटर की एमसीआरएल रेलवे लाइन का चरण-II पूरा किया जाना है। एमसीआरएल रेलवे लाइन के पूरा होने तक, एससीसीएल अस्थायी आधार पर सड़क/रेल मार्ग द्वारा विभिन्न विकल्पों की योजना बना रहा है।

रेलवे लाइन, रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट के निर्माण के अलावा प्री-वेट वैगन लोडिंग प्रणाली, क्रशर और एप्रोच रोड / बीटी रोड / डामर रोड की स्थापना की व्यवस्था

की जा रही है: कोयला परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण और रखरखाव आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

कोयला निकासी के लिए रेल और अवसंरचना परियोजना:

कोयला उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, एससीसीएल की कोयला प्रेषण क्षमता 100 मि.ट. है, एससीसीएल कोयला निकासी और अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कदम उठा रहा है –

चरण-II एफएमसी परियोजनाओं के अंतर्गत, वीके ओसी सीएचपी (06 एमटीपीए) और चरण-III के अंतर्गत, आरजी ओसी3 (5 एमटीपीए) सीएचपी की योजना बनाई गई है।



जेवीआर ओसी सीएचपी और रेलवे लाइन- कोयला निकासी के लिए अवसंरचना का विकास:

नये सीएचपी की ग्राउंडिंग

| क्रम सं. | सीएचपी/क्षेत्र | डिज़ाइन की गई क्षमता, एमटीपीए | आदेशित/ अनुमानित मूल्य (करोड़ में) | वर्तमान स्थिति | पीडीसी |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | आरजी2 का ओसी3 6सीएचपी | 05 | 161.94 | सीएचपी का निर्माण पीओ 7600009284, दिनांक: 25.10.2022 के अंतर्गत किया जा रहा है | 31.10.2024 (2024-25) |
| 2 | वीके7 सीएचपी, केजीएम | 06 | 332 | अंतिम निविदा दस्तावेज सीएमपीडीआई से प्राप्त किए जाने हैं। | 31.12.2026 (2026-27) |
| 3 | नैनी सीएचपी | 10 | 459 | सीएमपीडीआई को निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए टोस आदेश जारी | 31.03.2027 (2026-27) |

एनएलसीआईएल द्वारा किए गए प्रयास—

तालाबीरा II और III ओसीपी (20 एमटीपीए):

1. एफएमसी माइलस्टोन:

| परियोजना का नाम | कमीशनिंग के लिए अनुमानित समय—सीमा |
|--|-----------------------------------|
| खनन कार्य प्रारंभ | 2019–20 |
| सीएचपी, साइलो आधारित डिस्पैच और मैकेनाइज्ड कन्वेयर प्रणाली (एमडीओ) स्कोस्कोप | जून–2025 |
| रेलवे साइडिंग (एफएमसी) | जून 2025 |

2. **खनन कार्य प्रारंभ:** तालाबीरा II और III ओसीपी में कोयला उत्पादन 26.04.2020 से शुरू हुआ।

3. **सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और शीघ्र लदान साइलो:** सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और शीघ्र लदान साइलो का निर्माण एमडीओ के दायरे में है। एनएलसीआईएल द्वारा 07.10.2020 का अनुमोदन प्रदान किया गया है। एमडीओ द्वारा 29.10.2021 को एलओए जारी किया गया है।

4. **रेलवे साइडिंग (तालाबीरा—II और III ओसीपी):** प्रारंभ में, कोयले को सड़क मार्ग से पास की रेलवे साइडिंग तक ले जाया जाएगा, जहाँ से आगे पारादीप बंदरगाह तक ले जाया जाएगा, जहाँ से उसे एनटीपीएल, तूतीकोरिन भेजा जाएगा। तालाबीरा—II और III ओसीपी पर एक निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। कोयले को मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली के माध्यम से पिट हेड कोल स्टॉकयार्ड से रेलवे साइडिंग तक ले जाया जाएगा। कोयले को कम्प्यूटरीकृत शीघ्र लदान प्रणाली (साइलो) के माध्यम से रेलवे वैगनों में लोड किया जाएगा। रेलवे साइडिंग के चालू होने के बाद, कोयले को पिट हेड कोल स्टॉकयार्ड से एनटीपीएल, तूतीकोरिन तक विभिन्न तरीकों जैसे कि मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली, रेल और समुद्र के माध्यम से ले जाया जाएगा, जिससे सड़क परिवहन पूरी तरह से टाला जाएगा। शीघ्र लदान साइलो प्रणाली का निर्माण एमडीओ के दायरे में है।



पचवारा दक्षिण ओसीपी (9 एमटीपीए):

- नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड और मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) का एक संयुक्त उद्यम है, जो झारखंड के दुमका जिले में 9 एमटीपीए क्षमता का पचवारा साउथ कोल ब्लॉक विकसित कर रहा है।
- पचवारा साउथ ओसीपी से कोयला उत्पादन मार्च 2025 से शुरू होने की उम्मीद है
- पचवारा कोयला क्षेत्र में तीन कोयला ब्लॉक हैं, जिनके नाम पचवारा उत्तर, मध्य और दक्षिण हैं।
- पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को क्रमशः समीपवर्ती पचवारा उत्तर और पचवारा सेंट्रल कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।
- वर्तमान में पचवारा कोयला क्षेत्र के साथ कोई रेल संपर्क नहीं है।
- मेल लाइन पूरी होने तक कुरवा स्टेशन पर वैकल्पिक रेलवे साइडिंग विकसित की जा रही है। दिसंबर 2024 तक इसके चालू होने की उम्मीद है।

पीएम गतिशक्ति एनएमपी

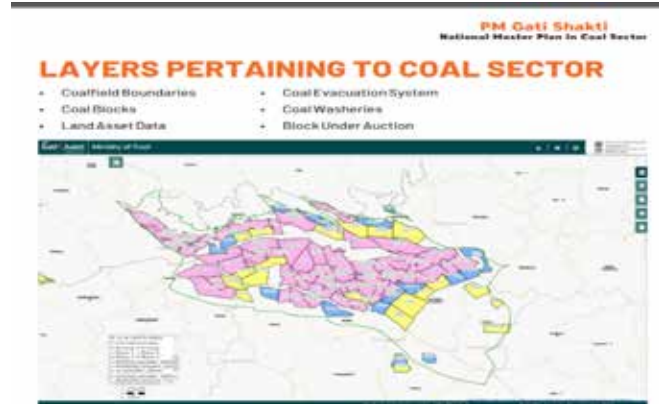
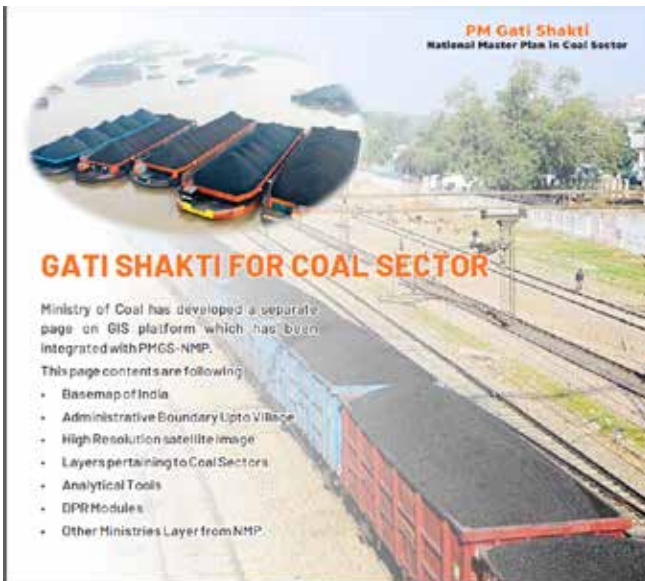
पीएम गतिशक्ति — राष्ट्र मास्टर प्लान (पीएमजीएस—एनएमपी) में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें स्थानिक आयोजन उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया



है। कोयला मंत्रालय ने विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ मैप किए गए 100 से अधिक डेटा परतों की पहचान की है। डेटा परतों की निगरानी की जा रही है और उन्हें आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार उनकी विशेषताओं के साथ आगे की परतें जोड़ी जा रही हैं। यह नियोजन चरण के दौरान संबंधित मंत्रालयों के संसाधनों की एकीकृत नियोजन प्रक्रिया को बढ़ाता है।

एनएमपी पोर्टल पर 74 परतों की मैपिंग की गई है। कोयला मंत्रालय ने धीरौली कोल ब्लॉक से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन के वैकल्पिक मार्ग, पेल्मा-सरडेगा और तंतुलोई-बुढापक लाइनों के वैकल्पिक रेल अलाइनमेंट के मुद्दों को हल करने के लिए पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल का उपयोग किया है ताकि कोल ब्लॉकों के साथ ओवरलैपिंग से बचा जा सके।

कोयला मंत्रालय का इरादा पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड और एप्लिकेशन के विकास और मंत्रालय के पोर्टल के साथ एकीकरण के माध्यम से कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं की खोज से लेकर योजना और निष्पादन तक कोयला संसाधन की मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। वर्तमान में, पोर्टल पर उपलब्ध भूमि संसाधनों का मानचित्रण किया जा रहा है। साथ ही, रेल मंत्रालय, बीआईएसएजी और सीएमपीडीआईएल के परामर्श से इन अवसंरचनाओं का मानचित्रण करके महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है।



कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति

कोयला आयात प्रतिस्थान के लिए कोयले की बाधा रहित निकासी अवाश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29 फरवरी 2024 को एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कोयला निकासी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, संधारणीय और विश्वसनीय लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस कार्यनीतिक ढांचे का उद्देश्य वित्त वर्ष 2030 में कोयला क्षेत्र की मांग और आपूर्ति को बढ़ाना है।

कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक योजना के निम्नलिखित केपीआई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है:

- वित्त वर्ष 2030 तक 90% कोयले के मशीनीकृत हैंडलिंग के लिए अवसंरचना का विकास करना।
- रेल मंत्रालय द्वारा नई/क्षमता वृद्धि लाइनों के रूप में रेल अवसंरचना का विकास करना।
- वित्त वर्ष 2030 तक तटीय शिपिंग के माध्यम से कोयले के परिवहन को बढ़ाकर 120 मि.ट. करना।
- वित्त वर्ष 2030 तक कोयले के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ाकर 8 मि.ट. करना।
- वित्त वर्ष 2030 तक निकासी के लिए 1 लाख वैगनों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
- स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड का विकास।